

Daily Current Affairs

Date : 19 February, 2026



अनुक्रमणिका

| क्र. सं. | टॉपिक का नाम |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 'सामाजिक सुरक्षा पेंशन' की राशि में वृद्धि |
| 2. | राजस्थान में 'नेक्स्ट जनरेशन सिटीजन सर्विस रिफॉर्म्स' |
| 3. | न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. निर्मल गोयल - प्रिंट श्री पुरस्कार 2025 2. सूर्यकिरण और सारंग एरोबेटिक शो : जयपुर 3. हथिनीकुंड बैराज 4. जयपुर शहर के लिए 'कॉम्प्रीहेंसिव मोबिलिटी प्लान (CMP)' 5. 'सहकार मंथन' बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व 6. राजस्थान मेंटल अवेयरनेस, मेंटरिंग एण्ड ट्रीटमेंट फॉर ऑल (Raj-MAMTA) प्रोग्राम 7. डॉ. तारकेश्वर जैन - राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (NCH) के अध्यक्ष |
| 4. | रॉयल इंडियन नेवी (RIN) विद्रोह: 80 वर्ष |
| 5. | ग्रेट निकोबार परियोजना |
| 6. | भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, 2025 |
| 7. | भारत और फ्रांस संबंध |
| 8. | सही (SAHI) और बोध (BODH) स्वास्थ्य AI पहल |
| 9. | 13 वाँ मिलान अभ्यास, 2026 |
| 10. | संयुक्त राष्ट्र फेलोशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम, 2026 |
| 11. | 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 2026 |
| 12. | न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. मिलानो कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक, 2026 2. प्रमोद भगत |

--:1:--



राजस्थान परिदृश्य



'सामाजिक सुरक्षा पेंशन' की राशि में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राजस्थान सरकार ने 'सामाजिक सुरक्षा पेंशन' की राशि में वृद्धि किए जाने की घोषणा की। यह वृद्धि राशि 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी मानी जाएगी लेकिन फरवरी, 2026 से देय होगी।

Increase in the amount of 'Social Security Pension'



मुख्य बिन्दु:

- ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान की जाने वाली ₹1250 की राशि ₹1300 हो गई है।
- लाभान्वित वर्ग : वृद्ध, विधवा या एकल नारी, दिव्यांगजन तथा लघु एवं सीमान्त कृषक।

--2--

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

- **इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना** : इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों के 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के सदस्यों को प्रति माह ₹1,250 (वर्तमान में ₹1300) की पेंशन प्रदान की जाती है।
- इसमें केंद्र सरकार 80 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को ₹200 प्रतिमाह और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को ₹500 प्रतिमाह का अंशदान देती है, जबकि शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।
- **मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना** : इस योजना के अन्तर्गत 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओं एवं 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुषों को, जिनकी सभी स्रोतों से परिवार की वार्षिक आय ₹48,000 से कम है, वृद्धावस्था सम्मान पेंशन के रूप में ₹1,250 प्रतिमाह (वर्तमान में ₹1300) प्रदान किये जाते हैं।
- **इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना** : इस योजना के तहत, बी.पी.एल. परिवारों की 40 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 40 वर्ष से अधिक लेकिन 75 वर्ष से कम आयु वर्ग की विधवाओं को ₹1,250 प्रति माह (वर्तमान में ₹1300) तथा 75 वर्ष और उससे अधिक आयु की विधवाओं को ₹1,500 प्रति माह प्रदान किए जाते हैं।
- केंद्र सरकार द्वारा 80 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों के लिए ₹300 और 80 वर्ष से अधिक आयु के लिए ₹500 का अंशदान दिया जाता है तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

Daily Current Affairs

Date : 19 February, 2026



- **मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना** : इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक लेकिन 75 वर्ष से कम आयु वर्ग की विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं को ₹1,250 प्रति माह (वर्तमान में ₹1300) तथा 75 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह पेंशन प्रदान की जा रही है। इस योजना के लिए पात्रता परिवार की वार्षिक आय ₹48,000 से कम होने पर आधारित है।
- **लघु एवं सीमांत वृद्ध किसान सम्मान पेंशन योजना**
- **राशि** : ₹1,250 (वर्तमान में ₹1300) प्रतिमाह।
- **पात्रता** : लघु एवं सीमांत किसान (महिलाएँ : 55 वर्ष या उससे अधिक आयु) (पुरुष : 58 वर्ष या उससे अधिक आयु)।

UTKARSH

CIVIL SERVICES

--:4:--

राजस्थान में 'नेक्स्ट जनरेशन सिटीजन सर्विस रिफॉर्म्स'

चर्चा में क्यों?

- वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा राजस्थान बजट 2026-27 में राज्य के निवासियों को त्वरित एवं प्रभावी सुविधाएँ सुनिश्चित करने के क्रम में 'नेक्स्ट जनरेशन सिटीजन सर्विस रिफॉर्म्स' की घोषणा की गई।



बजट 2026-27 में
प्रदेशवासियों को त्वरित एवं प्रभावी
सुविधाएं सुनिश्चित करने के क्रम में

नेक्स्ट जनरेशन सिटीजन
सर्विस रिफॉर्म्स की घोषणा

इसके अंतर्गत वनस ओनली प्रिंसिपल
को किया जा रहा है लागू

- इसमें नागरिकों एवं उद्यमियों से सिर्फ एक बार ही दस्तावेज लिया जाएगा, जिसे विभाग आपस में साझा करेंगे
- इसी प्रकार, लोक कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता निर्धारण को बेहतर बनाने के लिए जनाधार डेटाबेस को विभिन्न विभागों के मापदंडों और पोर्टल्स से जोड़ने का प्रावधान

इससे पात्र नागरिकों को सेवाएं
समय पर हो सकेंगी उपलब्ध



--5--

मुख्य बिन्दु:

- इसके अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा 'वन्स ओनली प्रिंसिपल' को लागू किया जा रहा है। इसमें नागरिकों एवं उद्यमियों से सिर्फ एक बार ही दस्तावेज लिया जाएगा, जिसे विभाग आपस में साझा करेंगे।
- इसी प्रकार, लोक कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता निर्धारण को बेहतर बनाने के लिए जनाधार डेटाबेस को विभिन्न विभागों के मापदंडों और पोर्टल्स से जोड़ने का प्रावधान भी किया गया है। इससे पात्र नागरिकों को समय पर सेवाएँ उपलब्ध हो सकेगी।
- राज्य सरकार ने डिजिटल राजस्थान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इनफ़ोर्मेशन एण्ड टेक्नॉलॉजी पॉलिसी की घोषणा की है।
- वहीं, स्टेट डेटा सेंटर की विभिन्न सेवाएँ स्टार्टअप्स, एमएसएमई और नागरिकों को किफायती दर पर उपलब्ध कराने के लिए 'डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटेशन पॉलिसी' की घोषणा की गई है।
- आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन, कृषि एवं पर्यावरण निगरानी में निर्णय क्षमता संवर्धन के लिए 'जिओ स्पेसियल पॉलिसी' की घोषणा की गई है।
- बजट 2026-27 में सुशासन और जनसहभागिता को प्रोत्साहित करने हेतु 'राजस्थान जन विश्वास अधिनियम 2.0' की घोषणा की गई है।
- **नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी टेक्नो हब** : राजस्थान बजट 2026-27 में कोटा में अत्याधुनिक तकनीकों के विकास के लिए नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी टेक्नो हब स्थापित किए जाने की घोषणा।
- **सीएम-प्रमाण** : राज्य में परिणामोन्मुखी जनकल्याणकारी योजनाओं और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए सीएम-प्रमाण (पॉलिसी, रिसर्च एण्ड एनालिटिक्स फोर मेजरेबल एक्शन एण्ड नेक्सस) यूनिट स्थापित की जाएगी।

Daily Current Affairs

Date : 19 February, 2026



- **RITI** : नीति आयोग की तर्ज पर 'राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एण्ड इनोवेशन (RITI) की स्थापना की गई है।
- **राजकिसान साथी पोर्टल** : राज्य के किसानों को "Ease of Doing Farming" (खेती करने में सुगमता) के लिए राजकिसान साथी पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म के माध्यम से कृषि, बागवानी और पशुपालन से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ सीधे डिजिटल माध्यम से लिया जा सकता है।
- **जन सूचना और संपर्क पोर्टल** : राजस्थान संपर्क पोर्टल (181 हेल्पलाइन) और जन सूचना पोर्टल के माध्यम से शिकायतों का ऑनलाइन समाधान और सूचनाओं की पारदर्शी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
- राज्य सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस फ्रेमवर्क को उन्नत करते हुए राजस्थान सम्पर्क 2.0 शुरू किया है।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

--7--

✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

| क्र. सं. | न्यूज़ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p>रा निर्मल गोयल - प्रिंट श्री पुरस्कार 2025</p> <ul style="list-style-type: none">ऑफसेट प्रिंटर्स एसोसिएशन की ओर से वर्ष 2025 का प्रिंट श्री पुरस्कार जयपुर निवासी पॉपुलर प्रिंटर्स के निर्मल गोयल को दिया जाएगा। |
| 2. | <p>सूर्यकिरण और सारंग एरोबेटिक शो : जयपुर</p> <ul style="list-style-type: none">आयोजन : 20 एवं 22 फरवरी, 2026आयोजक : भारतीय वायु सेना की सूर्यकिरण और सारंग एरोबेटिक टीम।आयोजन स्थल : जल महल की पाल, जयपुर। |
| 3. | <p>हथिनीकुंड बैराज</p> <ul style="list-style-type: none">हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से हासियावास (चूरू) तक लगभग 265 किलोमीटर लंबी तीन समानांतर पाइपलाइनों के एलाइनमेंट द्वारा जल आपूर्ति की जाएगी।राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच 17 फरवरी, 2024 को एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे 32 साल पुराने जल विवाद को सुलझाने का रास्ता साफ हुआ।इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान बजट 2026-27 में ₹32,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके तहत राजस्थान को मानसून के दौरान (जुलाई से अक्टूबर) 577 MCM (मिलियन क्यूबिक मीटर) पानी मिलेगा। |
| 4. | <p>जयपुर शहर के लिए 'कॉम्प्रीहेंसिव मोबिलिटी प्लान (CMP)'</p> <ul style="list-style-type: none">हाल ही में, जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) द्वारा जयपुर शहर के लिए कॉम्प्रीहेंसिव मोबिलिटी प्लान (CMP) का प्रारूप तैयार किया गया।इस महत्वपूर्ण योजना का उद्देश्य शहर में सुगम, सुरक्षित, समावेशी और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करना है। |

| | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | <p>'सहकार मंथन' बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व</p> <ul style="list-style-type: none">17 फरवरी, 2026 को गुजरात के गाँधीनगर में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 'सहकार मंथन' बैठक का आयोजन किया गया।इस बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक द्वारा किया गया। |
| 6. | <p>राजस्थान मेंटल अवेयरनेस, मेंटरिंग एण्ड ट्रीटमेंट फॉर ऑल (Raj-MAMTA) प्रोग्राम</p> <ul style="list-style-type: none">राजस्थान सरकार द्वारा अवसाद, चिंता एवं आत्महत्या की रोकथाम हेतु राज्य बजट 2026-27 में 'राजस्थान मेंटल अवेयरनेस, मेंटरिंग एण्ड ट्रीटमेंट फॉर ऑल (Raj-MAMTA)' प्रोग्राम की घोषणा की गई।इसके अंतर्गत काउन्सलिंग, टेली-मेडिसिन की सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी। साथ ही, जयपुर में 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ' की स्थापना होगी। |
| 7. | <p>डॉ. तारकेश्वर जैन - राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (NCH) के अध्यक्ष</p> <ul style="list-style-type: none">केंद्र सरकार द्वारा जयपुर निवासी डॉ. तारकेश्वर जैन को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (NCH) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। |

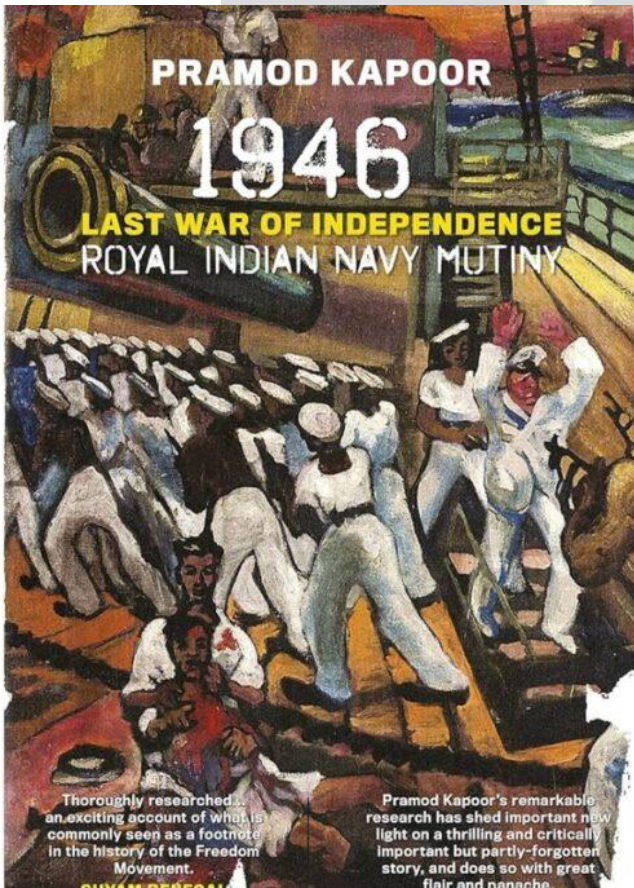


इतिहास एवं संस्कृति

रॉयल इंडियन नेवी (RIN) विद्रोह: 80 वर्ष

चर्चा में क्यों?

- 18 फरवरी, 2026 को रॉयल इंडियन नेवी (RIN) के वर्ष 1946 के विद्रोह की 80 वीं वर्षगाँठ मनाई गई।



मुख्य बिन्दु:

रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, 1946:

- परिचय:** RIN विद्रोह (वर्ष 1946) नस्लीय भेदभाव और INA मुकदमों के खिलाफ 20,000 भारतीय नौसैनिकों द्वारा किया गया पाँच दिवसीय सशस्त्र विद्रोह (18 से 23 फरवरी, 1946) था।

Daily Current Affairs

Date : 19 February, 2026



- **तात्कालिक कारण:** यह विद्रोह बंबई में एचएमआईएस तलवार जहाज पर काम करने वाले नाविकों द्वारा खराब भोजन की गुणवत्ता, कम वेतन, नस्लीय भेदभाव, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार और जहाज पर 'भारत छोड़ो' लिखने के आरोप में एक नाविक की गिरफ्तारी के विरोध में भड़का था।
- **संबद्ध नेता:** बी.सी. दत्त, एम.एस. खान, मदन सिंह, सलिल श्याम और ऋषि देव।
- **आरंभिक चरण ; शुरुआत:** 18 फरवरी, 1946 को HMIS तलवार (बॉम्बे) में खराब खाद्य गुणवत्ता के विरोध में भूख हड़ताल से हुई थी।
 - कार्रवाईयों के समन्वय और माँगों को प्रस्तुत करने के लिए मुंबई के मरीन ड्राइव में स्थापित, प्राण और कुसुम नायर के नेतृत्व में एक नौसेना केंद्रीय स्ट्राइक समिति का गठन किया गया।
- **विस्तार:** यह कराची, मद्रास, कोचीन, विशाखापत्तनम, कलकत्ता और अंडमान द्वीप समूह के नौसैनिक अड्डों तक फैल गया, जिसमें 78 जहाज और 20 तटीय प्रतिष्ठान शामिल थे।
 - जनसमर्थन: कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे एक साथ फहराए जाने से हिंदू-मुस्लिम एकता स्पष्ट रूप से दिखाई दी।
 - कांग्रेस का समर्थन: सितंबर, 1945 में बॉम्बे अधिवेशन में कांग्रेस ने INA के समर्थन में एक सशक्त प्रस्ताव पारित किया। INA की रक्षा का आयोजन भुलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू और आसफ अली ने किया था।
- **विद्रोह का अंत:** सरदार पटेल और मुहम्मद अली जिन्ना द्वारा विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी करने और उन्हें यह आश्वासन देने के बाद कि राष्ट्रीय पार्टियाँ किसी भी प्रकार के उत्पीड़न को रोकेंगी, विद्रोह 23 फरवरी, 1946 को समाप्त हो गया।

-:11:-

Daily Current Affairs

Date : 19 February, 2026



अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA):

- **परिचय:** INA द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय युद्धबंदियों (पीओडब्ल्यू) द्वारा गठित एक सैन्य बल था, जिसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था।
- **गठन:** शुरुआत में मोहन सिंह द्वारा जापानी समर्थन से प्रस्तावित सैनिकों की भर्ती की गई। बाद में रासबिहारी बोस ने टोक्यो में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की (वर्ष 1942)।
- **सुभाष चंद्र बोस द्वारा नेतृत्व:** सुभाष चंद्र बोस ने 25 अगस्त, 1943 को कमान संभाली और सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की (21 अक्टूबर, 1943), जिसे जापान और जर्मनी सहित 9 देशों द्वारा मान्यता प्राप्त थी।
- **अभियान:** 'चलो दिल्ली' अभियान शुरू किया, मणिपुर के मोइरांग में झंडा फहराया।
- **पतन:** जापान के आत्मसमर्पण (15 अगस्त, 1945) और ताइवान में विमान दुर्घटना में बोस की कथित मृत्यु (18 अगस्त, 1945) के बाद अभियान का पतन हो गया।
- **INA मुकदमे (लाल किला):** प्रेम कुमार सहगल (हिंदू), शाह नवाज़ खान (मुस्लिम) और गुरबख्श सिंह ढिल्लों (सिख) के खिलाफ लाल किले में पहला मुकदमा (नवंबर, 1945) चला, जो एकता का प्रतीक था। उनका बचाव भुलाभाई देसाई, तेज बहादुर संप्र, जवाहरलाल नेहरू और आसफ अली ने किया।
- बॉम्बे कांग्रेस अधिवेशन (सितंबर, 1945) में कैदियों का समर्थन किया गया।
- **प्रमुख विद्रोह (1945-46):** 21 नवंबर, 1945 (कलकत्ता), 11 फरवरी, 1946 (कलकत्ता में राशिद अली के विरुद्ध) और 18 फरवरी, 1946 (रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह, बंबई) तीन हिंसक झड़पें हुईं।

--:12:--

भूगोल एवं भू-विज्ञान

ग्रेट निकोबार परियोजना

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने 81,000 करोड़ रुपये की ग्रेट निकोबार परियोजना को मंजूरी दे दी है।

मुख्य बिन्दु:

- NGT के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय विशेष पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि यह परियोजना महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित में है, जिसका पर्यावरणीय प्रभावों के साथ-साथ मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- इस पीठ में न्यायिक सदस्य दिनेश कुमार सिंह और अरुण कुमार त्यागी तथा विशेषज्ञ सदस्य सेंथिल वेल, अफरोज अहमद और ईश्वर सिंह शामिल थे।
- 81,000 करोड़ रुपये की इस परियोजना को औपचारिक रूप से ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का समग्र विकास कहा जाता है और यह द्वीप के 166 वर्ग किलोमीटर के हरे-भरे उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र में फैली हुई है। इसमें एक अंतरराष्ट्रीय माल ढुलाई बंदरगाह, एक गैस और सौर ऊर्जा संयंत्र, नागरिक और सैन्य उपयोग के लिए एक हवाई अड्डा और एक विशाल टाउनशिप का निर्माण शामिल है।

राष्ट्रीय पर्यावरण परिषद (एनजीटी) द्वारा सुझाएँ गए पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय:

1. **शर्तों की बाध्यकारी प्रकृति:** सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि परियोजना कार्यान्वयन के किसी भी चरण में इनका उल्लंघन न हो।
2. **तट कटाव की रोकथाम और रेतीले समुद्र तटों का संरक्षण:** NGT निर्देशानुसार परियोजना क्षेत्र के पास या किसी भी द्वीप के किनारे कटाव या प्रतिकूल तटरेखा परिवर्तन का कारण नहीं बनना चाहिए।
3. **प्रवाल भित्तियों का संरक्षण:** NGT ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) को में प्रवाल भित्तियों की रक्षा तथा वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से प्रवाल पुनर्जनन का आदेश दिया, साथ ही मौजूदा बिखरे हुए प्रवाल को भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) के सुझावों के अनुसार स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
4. **लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण:** निकोबार मेगापोड, निकोबार मैकाक, लेदरबैक समुद्री कछुए, खारे पानी के मगरमच्छ और अन्य स्थानिक पक्षी प्रजातियों के संरक्षण के लिए विशिष्ट शर्तें शामिल हैं।

ग्रेट निकोबार परियोजना:

- **परिचय:** भारत के समुद्री विजन, 2030 और अमृत काल विजन, 2047 के अनुरूप ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के सबसे दक्षिणी द्वीप को एक रणनीतिक और आर्थिक केंद्र में परिवर्तित करने के लिए शुरू की गई हैं, जिसमें गलाथिया खाड़ी, पेम्माया खाड़ी और नांजप्पा खाड़ी का विकास तथा गैलाथिया बे नेशनल पार्क और कैम्बेल बे नेशनल पार्क का 10 किमी क्षेत्र शामिल है।
- **पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मंजूरी:** नवंबर, 2022 (परिकल्पना: वर्ष 2015 में नीति आयोग द्वारा)।
- **परियोजना का संचालन:** नीति आयोग
- **नोडल एजेंसी:** अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम (ANIIDCO)

Daily Current Affairs

Date : 19 February, 2026

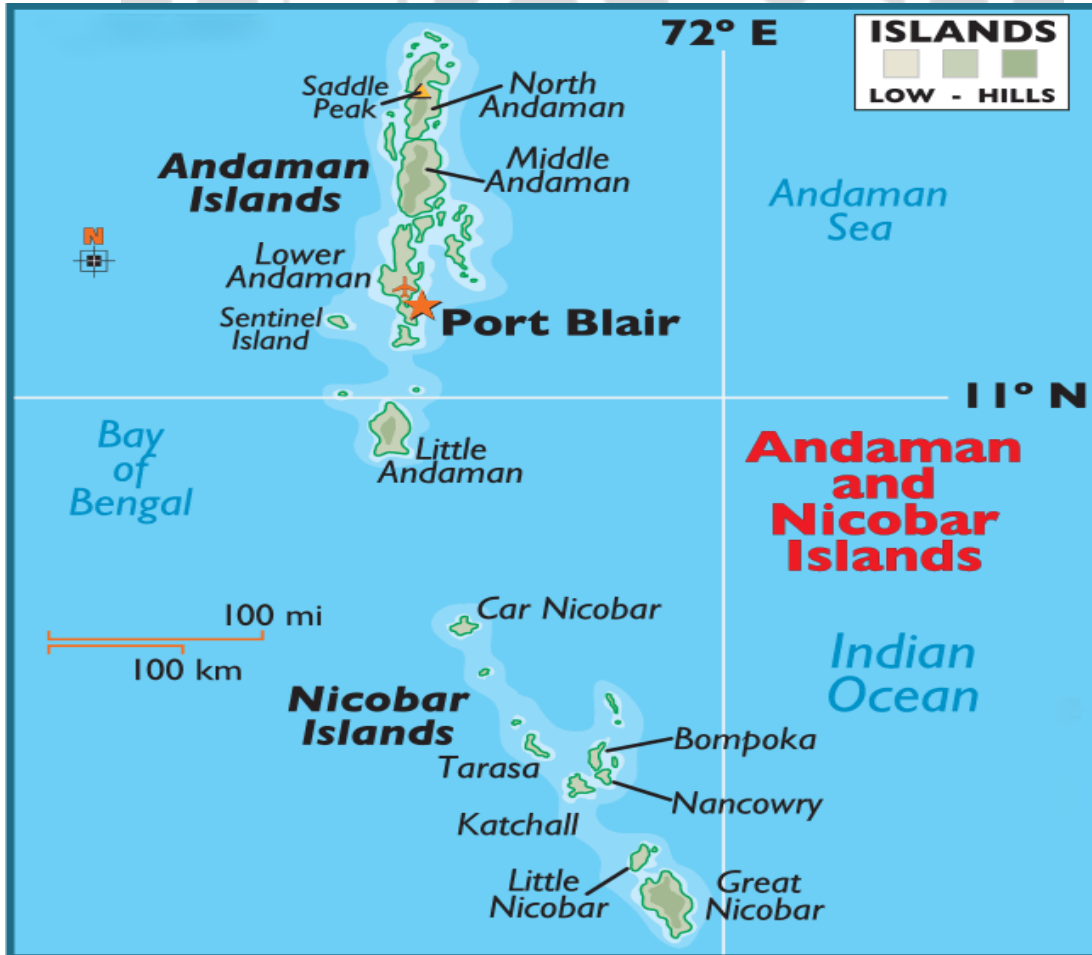


■ प्रमुख अवसंरचना घटक:

1. अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल/ICTT (वैश्विक समुद्री अर्थव्यवस्था का विकास)
2. ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट (कनेक्टिविटी और पर्यटन)
3. ग्रीनफील्ड टाउनशिप
4. गैस और सौर ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्र
5. जनजातीय सुरक्षा (अनुच्छेद 338A(9) के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की परामर्श से जनजातीय हितों की रक्षा)
6. पर्यावरण संरक्षण उपाय (8 वन्यजीव गलियारे)

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:

ग्रेट निकोबार द्वीप:



-:15:-

Daily Current Affairs

Date : 19 February, 2026



- **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह:** इसमें 836 द्वीप शामिल हैं, जो भौगोलिक रूप से उत्तर में अंडमान समूह और दक्षिण में निकोबार समूह में दस डिग्री चैनल द्वारा विभाजित हैं, जो लगभग 150 किमी चौड़ा है।
- **ग्रेट निकोबार द्वीप:** यह निकोबार द्वीपसमूह का सबसे बड़ा द्वीप है, जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय वर्षावन से ढका हुआ है। यहाँ इंदिरा प्वाइंट स्थित है, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है और इंडोनेशिया के सुमात्रा से मात्र 90 समुद्री मील की दूरी पर है।
- **पारिस्थितिक महत्व:** यह द्वीप कैम्पबेल राष्ट्रीय उद्यान और गलाथिया बे राष्ट्रीय उद्यान। इसमें ग्रेट निकोबार जीवमंडल अभयारण्य भी शामिल है, जिसे वर्ष 2013 में यूनेस्को के मानव और जीवमंडल कार्यक्रम में शामिल किया गया था।
- **जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल:** शोम्पेन, निकोबारी, ओंगे और अंडमानी जनजातीय समुदाय।
- **जनजातीय मुद्दा:** लगभग 9.64 लाख पेड़ों को काटे जाने की आशंका है। जो द्वीप के क्षेत्रफल का लगभग 15% हैं।
- इस क्षेत्र में वर्ष 2004 में भूकंप (रिक्टर स्केल पर 9.2 तीव्रता का) आया था।

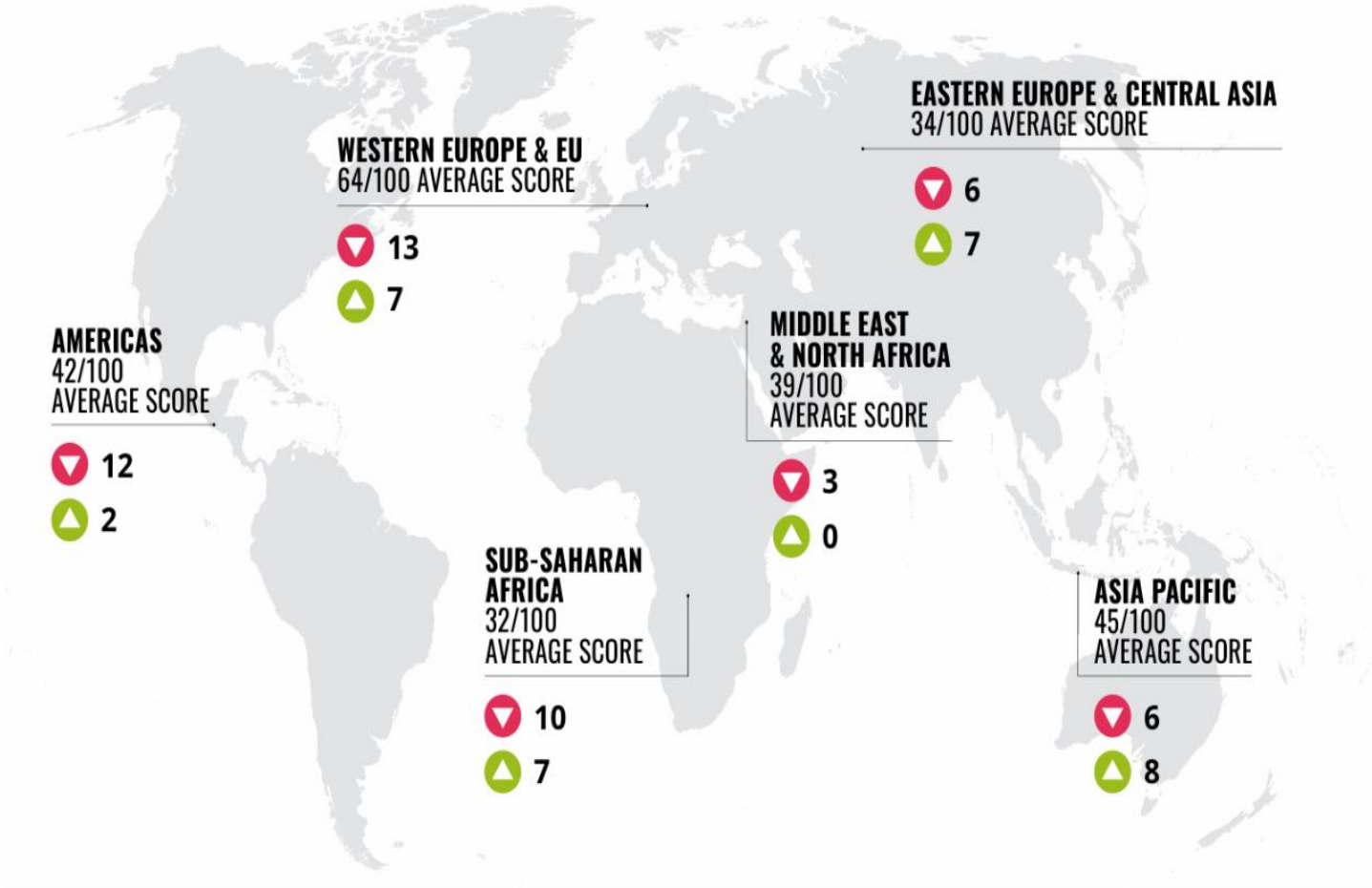
-:16:-

लोक प्रशासन

भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, 2025

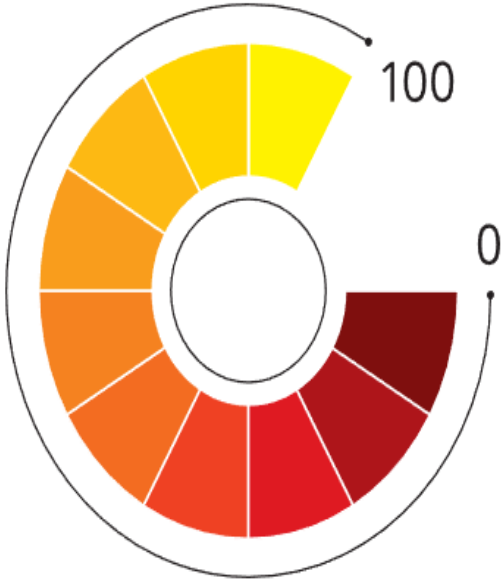
चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI), 2025 में भारत 39/100 के स्कोर के साथ 91वें स्थान पर रहा, जो वर्ष 2024 में इसके 96वें स्थान से थोड़ा बेहतर है।



मुख्य बिन्दु:

- इसमें सार्वजनिक क्षेत्र में कथित भ्रष्टाचार के आधार पर 182 देशों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें शून्य (अत्यधिक भ्रष्ट) से लेकर 100 (बहुत साफ) तक के पैमाने का उपयोग किया गया।



THE CPI USES A SCALE FROM 0 TO 100

100 is **very clean** and
0 is **highly corrupt**

निष्कर्ष:

- **वैश्विक औसत में गिरावट:** एक दशक से अधिक समय में पहली बार, वैश्विक CPI औसत 100 में से घटकर मात्र 42 रह गया है। अधिकांश देशों (182 में से 122 देश) का स्कोर 50 से नीचे है, जो विश्व स्तर पर भ्रष्टाचार की गंभीर समस्याओं को दर्शाता है।
- **उच्च प्रदर्शन देश:** 80 से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले देशों की संख्या एक दशक पहले 12 से घटकर इस वर्ष केवल 5 रह गई है (डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, नॉर्वे)।
- **शीर्ष और निम्नतम प्रदर्शनकर्ता:** डेनमार्क (स्कोर - 89) लगातार आठवीं बार शीर्ष स्थान पर है, जबकि सोमालिया और दक्षिण सूडान (9) सबसे निचले पायदान पर हैं।

Daily Current Affairs

Date : 19 February, 2026

UTKARSH
CLASSES

CIVIL
SERVICES

विभिन्न देशों की स्थिति:

| अंक | | देश | रैंक |
|-----|---|---------------|------|
| 89 | ↓ | डेनमार्क | 1 |
| 88 | = | फिनलैंड | 2 |
| 84 | = | सिंगापुर | 3 |
| 81 | ↓ | न्यूज़ीलैंड | 4 |
| 81 | = | नॉर्वे | 4 |
| 80 | = | स्वीडन | 6 |
| 80 | ↓ | स्विट्ज़रलैंड | 6 |
| 78 | ↓ | लक्समबर्ग | 8 |
| 78 | = | नीदरलैंड | 8 |
| 77 | ↑ | जर्मनी | 10 |
| 77 | = | आइसलैंड | 10 |

--:19:--



Daily Current Affairs

Date : 19 February, 2026



भारत के संदर्भ में आँकलन:

- **भारत (स्कोर 39, रैंक 91):** अधिकांश दक्षिण एशियाई पड़ोसियों से बेहतर प्रदर्शन करता है लेकिन भूटान (स्कोर 71, रैंक 18) और चीन (स्कोर 43, रैंक 76) से पीछे हैं।
- भारत मालदीव (स्कोर 39, रैंक 91) के साथ बराबरी पर है।
- **अन्य देश निचले पायदान पर हैं:** श्रीलंका (स्कोर 35, रैंक 107), नेपाल (स्कोर 34, रैंक 109), पाकिस्तान (स्कोर 28, रैंक 136), बांग्लादेश (स्कोर 24, रैंक 150), अफगानिस्तान और म्यांमार (स्कोर 16, रैंक 169) के साथ।
- **रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के कारण:** कमजोर न्याय व्यवस्था और विधि का शासन, राजनीतिक निर्णय लेने पर अनुचित प्रभाव, नागरिक स्वतंत्रता और मीडिया की स्वतंत्रता का संकुचन और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में विफलताएँ आदि।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

--:20:--



अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य



भारत और फ्रांस संबंध

चर्चा में क्यों?

- 17 से 19 फरवरी, 2026 तक फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भारत की औपचारिक यात्रा सम्पन्न की। यह राष्ट्रपति मैक्रों का भारत का चौथा दौरा था।



Daily Current Affairs

Date : 19 February, 2026



मुख्य बिन्दु:

यात्रा के परिणाम:

| शीर्षक | क्षेत्र |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| उन्नत साझेदारी और 'होराइजन 2047' रोडमैप के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा के लिए वार्षिक विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता की शुरुआत (होराइजन 2047 रोडमैप: वर्ष 2023 में अपनाई गई यह योजना अगले 25 वर्षों के लिए मार्ग प्रशस्त करती है, जो भारत की स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के साथ मेल खाती है।) रणनीतिक साझेदारी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नमस्ते फ्रांस 2028 | राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध |
| भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष का शुभारंभ भारत-फ्रांस इनोवेशन नेटवर्क का शुभारंभ | तकनीक और नवाचार |
| कर्नाटक के वेमागल में H125 हेलीकॉप्टर बनाने की फैक्ट्री (असेम्बली लाइन) का उद्घाटन; भारत में निजी क्षेत्र की पहली हेलीकॉप्टर सुविधा। | रक्षा और सुरक्षा |
| 26 राफेल-मरीन लड़ाकू जेट विमानों की खरीद का अनुबंध भारत में हैमर मिसाइल बनाने के लिए BEL और सैफरान के बीच जॉइंट वेंचर | |
| क्रिटिकल मिनरल्स और मेटल्स में आपसी सहयोग हेतु संयुक्त घोषणा पत्र | रक्षा क्षेत्र सहित महत्वपूर्ण और उभरती हुई तकनीक |
| विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और फ्रांस के CNRS ने उन्नत सामग्री के क्षेत्र में अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए आपसी सहमति | |
| भारत और फ्रांस के बीच डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट पर प्रोटोकॉल में संशोधन | |

--:22:--

Daily Current Affairs

Date : 19 February, 2026



स्टार्टअप इकोसिस्टम, नवाचार और तकनीक में रणनीतिक सहयोग हेतु टी-हब (T-Hub) और नॉर्ड फ्रांस के बीच आशय पत्र पर हस्ताक्षर

अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, अक्षय ऊर्जा और कौशल विकास

डिजिटल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए इंडो-फ्रेंच सेंटर स्थापित करने हेतु संयुक्त आशय घोषणा

एम्स, नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई के लिए इंडो-फ्रेंच सेंटर का शुभारंभ

मेटाबॉलिक हेल्थ साइंसेज के लिए इंडो-फ्रेंच सेंटर की स्थापना हेतु समझौते पर हस्ताक्षर

एरोनॉटिक्स में कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने हेतु आशय पत्र पर हस्ताक्षर

जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना सहित मूल्य श्रृंखला में सहयोग तथा भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन (जुलाई, 2026, फ्रांस) में भाग लेगा।

वर्ष 2030 तक फ्रांस में 30,000 भारतीय छात्रों का लक्ष्य (वर्तमान 10,000 से)।

शिक्षा और संस्कृति

फ्रांस म्यूजियम्स डेवलपमेंट के सहयोग से युगे युगीन भारत संग्रहालय।

--:23:--



उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

⌚ विज्ञान प्रौद्योगिकी 🌡️

सही (SAHI) और बोध (BODH) स्वास्थ्य AI पहल

📌 चर्चा में क्यों?

- 17 फरवरी, 2026 को भारत मंडपम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इंडिया एआई समिट में दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल- भारत के स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की रणनीति (SAHI) और स्वास्थ्य आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के लिए बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म (BODH) का शुभारंभ किया।



📌 मुख्य बिन्दु:

- यह पहलें राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (वर्ष 2020) के दृष्टिकोण पर आधारित हैं।
- **नोडल मंत्रालय:** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW)।

Daily Current Affairs

Date : 19 February, 2026



- **भारत के स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की रणनीति (SAHI; सिव्योर एआई फॉर हेल्थ इनिशिएटिव):** भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सुरक्षित, नैतिक, साक्ष्य-आधारित और समावेशी रूप से अपनाने में सक्षम बनाने हेतु राष्ट्रीय मार्गदर्शन प्रारूप है।
 - इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधानों के संचालन, डेटा प्रबंधन, सत्यापन, अनुप्रयोग और निगरानी पर महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करना है, साथ ही राज्यों और संस्थानों को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के अनुरूप इसे दायित्वपूर्ण तरीके से अपनाने में सहायता करना है।
- **स्वास्थ्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म (BODH):** भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित स्वास्थ्य सेवा में एआई के लिए बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म (BODH) निजी गोपनीयता-सुरक्षित रखने वाला मानक प्लेटफॉर्म है, जो अंतर्निहित डेटासेट को साझा किए बिना विविध, वास्तविक स्वास्थ्य डेटा के उपयोग से एआई मॉडल के सटीक मूल्यांकन को सक्षम बनाता है।

--:25:--

13 वाँ मिलान अभ्यास, 2026

चर्चा में क्यों?

- भारतीय नौसेना ने अपने प्रमुख अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक 13वें मिलान अभ्यास, 2026 (15 से 25 फरवरी, 2026) के अंतर्गत 15 फरवरी, 2026 को पूर्वी नौसेना कमान में मिलान विलेज (विशाखापत्तनम) का अनावरण किया।
- 13 वें अभ्यास मिलान, 2026 में जर्मनी, फिलीपींस और संयुक्त अरब अमीरात जैसे पहली बार भाग लेने वाले देशों सहित 70 से अधिक देशों की भागीदारी है।



मुख्य बिन्दु:

- **परिचय:** मिलान (MILAN) भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक (हर दो वर्ष में एक बार) बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है।

Daily Current Affairs

Date : 19 February, 2026



- **शुरुआत:** वर्ष 1995 में अंडमान और निकोबार कमान के तहत शुरू मात्र चार विदेशी नौसेनाओं; इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड के साथ शुरू हुआ।
- **मुख्य उद्देश्य:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आयोजित होने वाले सबसे बड़े बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यासों में से एक मिलान, 2026 विश्व की अनेक नौसेनाओं को एक मंच पर लाएगा, ताकि आपसी सहभागिता, समुद्री क्षेत्र की जागरूकता और सामूहिक प्रतिक्रिया क्षमताओं को सुदृढ़ किया जा सके।
- **संरचनात्मक चरण:** इसमें दो मुख्य चरण शामिल हैं: अभ्यास के बंदरगाह और समुद्री चरण पनडुब्बी रोधी युद्ध, वायु रक्षा, खोज व बचाव तथा सहयोगात्मक सुरक्षा अभियानों सहित जटिल समुद्री परिचालनों पर केंद्रित होंगे, जो स्वतंत्र, खुले, समावेशी एवं नियम-आधारित समुद्री सीमा के प्रति साझा प्रतिबद्धता को और मजबूत करेंगे।
- **महत्त्व:** अभ्यास मिलान, 2026, अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा (IFR), 2026 और आयन्स कॉन्वलेव ऑफ चीफ्स के साथ मिलकर भारत के ऐतिहासिक समुद्री अभिसरण का एक प्रमुख स्तंभ बनेगा।

-:27:-

संयुक्त राष्ट्र फेलोशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम, 2026

चर्चा में क्यों?

- भारत एशिया में पहली बार एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए लघु शस्त्र और हल्के हथियार (SALW) नियंत्रण पर संयुक्त राष्ट्र के पहले फेलोशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है।
- यह कार्यक्रम विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में 16 फरवरी से 6 मार्च, 2026 तक मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित सैन्य सामग्री प्रबंधन महाविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है।



मुख्य बिन्दु:

- **परिचय:** छोटे हथियारों और हल्के हथियारों के नियंत्रण पर संयुक्त राष्ट्र का फैलोशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम एक तीन सप्ताह का क्षमता-निर्माण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य छोटे हथियारों और हल्के हथियारों के अवैध व्यापार और दुरुपयोग को नियंत्रित करने में सरकारी विशेषज्ञता को मजबूत करना है।
- **मेजबान:** भारतीय सेना
- **स्थान:** मिलिट्री कॉलेज ऑफ मैटेरियल्स मैनेजमेंट, जबलपुर, मध्य प्रदेश
- **आयोजन संस्थाएँ:**
 - संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण मामलों का कार्यालय (UNODA)
 - एशिया और प्रशांत क्षेत्र में शांति और निरस्त्रीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय केंद्र (UNRCPD)
- **उद्देश्य:** छोटे हथियारों (SALW) के अवैध व्यापार, दुरुपयोग और अवैध प्रवाह को रोकने के लिए सरकारी अधिकारियों की क्षमता को बढ़ाना।
- **भागीदार:** इस कार्यक्रम में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 13 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

खेल

12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 2026

चर्चा में क्यों?

- 6 से 8 फरवरी, 2026 तक चीन के तियानजिन में आयोजित एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 2026 में भारत ने पदक तालिका में छठा स्थान हासिल किया।



--:30:--

मुख्य बिन्दु:

- **शीर्ष स्थान:** मेजबान देश चीन ने चैंपियनशिप में 10 स्वर्ण, 11 रजत और 13 कांस्य सहित 34 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया।
- **भारत का प्रदर्शन:** भारत ने पांच पदक जीतकर पदक तालिका में छठा स्थान हासिल किया।
- **भारतीय पदक विजेता:**

| खिलाड़ी | पदक | विवरण |
|------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तेजस्विन शंकर (हेप्ताथलॉन) | स्वर्ण | तेजस्विन शंकर ने हेप्ताथलॉन में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 2026 में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। |
| तजिंदरपाल सिंह तूर (पुरुष शॉट पुट) | रजत | चीन के चेन चेंग्यू से हराने के पश्चात् रजत पदक हासिल किया। |
| पूजा (महिला ऊँची कूद) | रजत | एक राष्ट्रीय इनडोर रिकॉर्ड भी तोड़ा। |
| जे आदर्श राम (पुरुषों की ऊँची कूद) | कांस्य | एशियाई इनडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 2026 में भारत को पहला पदक दिलाया। |
| एंसी सोजन (महिला लंबी कूद) | कांस्य | पिछले वर्ष एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक भी जीता था। |

- पुरुषों के शॉटपुट स्पर्धा में भाग लेने वाले दूसरे भारतीय समरदीप गिल ने अपने अंतिम प्रयास में 18.97 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाकर पांचवां स्थान हासिल किया।

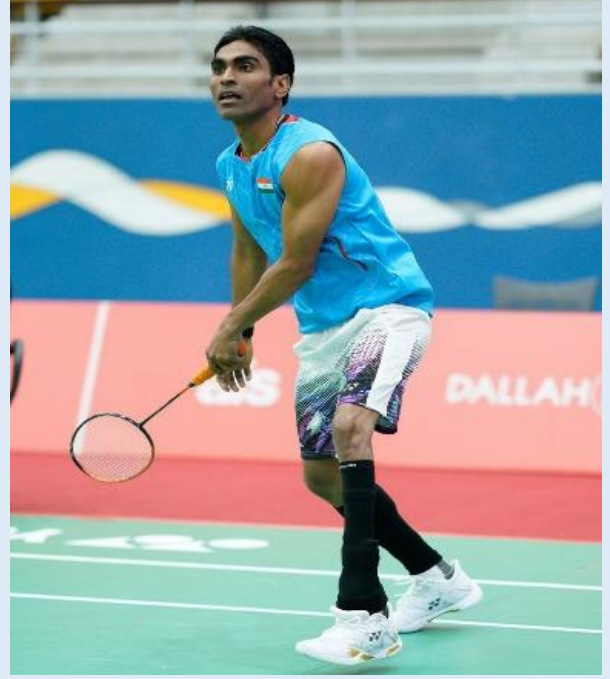
✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

| क्र. सं. | न्यूज़ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p>मिलानो कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक, 2026</p> <ul style="list-style-type: none">■ मिलानो कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक, 2026 में ब्राज़ील के स्कीयर लुकास पिनहेरो ब्राथेन ने जायंट स्लैलम में स्वर्ण पदक हासिल किया।  <ul style="list-style-type: none">■ उन्होंने 2 मिनट 25 सेकंड के कुल समय के साथ स्विट्जरलैंड के मौजूदा चैंपियन मार्को ओडरमैट को 0.58 सेकंड से हराया।■ जायंट स्लैलम अल्पाइन स्कीइंग और अल्पाइन स्नोबोर्डिंग की एक प्रतिस्पर्धी विधा है।■ भारत के आरिफ मोहम्मद खान अल्पाइन स्कीइंग के स्लैलम स्पर्धा में भाग लेंगे। इससे पहले, क्रॉस-कंट्री स्कीयर स्टैनज़िन लुंडुप पुरुषों की 10 किलोमीटर दौड़ में 104वें स्थान पर रहे। |

2.

प्रमोद भगत

- बहरीन में विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुषों के एस.एल-3 वर्ग में प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक हासिल किया।
- फाइनल में प्रमोद ने मोहम्मद अल इमरान को हराकर विश्व चैंपियनशिप में लगातार चौथा सिंगल्स स्वर्ण पदक जीता।
- प्रमोद के नाम अब कुल छह विश्व खिताब हो गए हैं। प्रमोद, चीन के लिन डैन को पछाड़ते हुए पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन के इतिहास में सबसे सफल खिलाड़ी बन गए हैं।



UTKARSH
CIVIL
SERVICES